साप्ताहिक

# जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 27 फरवरी-05 मार्च, 2023, वर्ष-8, अंक-46

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

### 2020 में मध्यप्रदेश में 235 किसानों की आत्महत्या पर पुलिस कर रही जांच

## किसान आत्महत्या में अलीराजपुर पहले और सीधी दूसरे नंबर पर

भोपाल। जागत गांव हमार

राज्य सरकार के लाख प्रयास के बाद भी किसानों की आत्महया का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आंकड़े बताते हैं कि किसान आत्महत्या में अलीराजपुर पहले और सीधी जिला दूसरे नंबर पर है। अलीराजपुर में 67, सीधी में 27, दतिया में 19, अशोकनगर में 14, बड़वानी में 13, सतना में 14, शिवपुरी में 13, सिंगरौली में 9, सागर में 9, उमरिया में 9, शहजहांपुर में 7, नीमच में 4, ग्वालियर में 3, खरगोन में 3, दमोह में 3 और मुरैना में 3 किसानों ने आत्महत्या की है। 2020 में करीब 235 किसानों ने आत्महत्या की थीं। इन आत्महत्याओं की जांच पुलिस ने 22 जिलों में की। जो जांच रिपोर्ट बनी, उसके मुताबिक किसानों ने मुख्यत: तीन कारणों से मौत को गले लगाया। सबसे ज्यादा 73 किसानों ने पारिवारिक कारणों से आत्महत्या की, जबकि 55 की मौत पागलपन या मानसिक बीमारी के चलते हुई। वहीं अलीराजपुर के एसपी मनोज सिंह का कहना है कि इस साल अब तक आलीराजपुर में 50 किसान सुसाइड कर चुके हैं। 23 की मौत शराब की लत से हुई।

### अलीराजपुर में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं

पागलपन या मानसिक बीमारी के कारण अलीराजपुर में 32, सीहोर 7, सीधी 5, सिंगरौली 3, उमरिया 4 और ग्वालियर, उज्जैन, शाहजहांपुर, नीमच में 1-1 किसान आत्महत्या हुईं। नशीली दवाओं के चलते अलीराजपुर में 19,सीहोर, शहडोल व सीधी 3-3, सिंगरौली 3, उमरिया 5 व टीकमगढ़ व शिवपुरी में 2-2 किसानों ने जान दी। पारिवारिक समस्या के कारण अलीराजपुर में 16, अशोक नगर में 12, बड़वानी में 13, सागर में 7, शिवपुरी में 6, सिंगरौली में 4, विदिशा में 3 सुसाइड हुईं।

**दिवालियापन में भी दी जान** | 40 किसानों ने नशीली दवाओं की लत के चलते आत्महत्या की। पुलिस ने अपनी जांच मुख्यत: 16 बिंदुओं पर की। इनमें पागलपन- मानसिक रोगी और नशीली दवाओं का दुरुपयोग या लत, सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट, दिवालियापन, गरीबी, संपत्ति विवाद, विवाह , दहेज, अतिरिक्त विवाह संबंधी, तलाक, पारिवारिक समस्या, खेती, फसल विफलता, प्राकृतिक आपदा, खेती संबंधित मुद्दे, बीमारी, एड्स, कैंसर जैसे कारण शामिल थे।

**कर्ज से ही टूटता है किसान** | इधर, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा ने कहा कि किसान की मौत का सबसे बड़ा कारण कर्जा व फसल बेचने में परेशानी है। किसान जीवटता का प्रतीक है। अंग्रेजों के जमाने में किसान दंडित, प्रताड़ित व अपमानित हुआ पर टूटा नहीं, लेकिन अब अन्नदाता परास्त हो गया। खेत सूखने लगे, कर्ज बढ़ने लगे और फसल नहीं बिके तो चारों तरफ हताशा छा जाती है।

### 30 वर्ष पुराने 15 बीज, 10 रुपए लगती है टिकट

## कुसमी के खोखरा में प्रसंस्करण यंत्र, कृषि यंत्र रखे

## सीधी में देश का पहला 'श्री अन्न' संग्रहालय

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश का पहला अनूठा श्री अन्न संग्रहालय (म्यूजियम) सीधी जिले के आदिवासी बहुल कुसमी के खोखरा गांव में बनाया गया है। इस संग्रहालय में वर्षों पुराने श्री अन्न, प्रसंस्करण यंत्र, कृषि यंत्र, पौधे रखे गए हैं। विदेशी पर्यटक संग्रहालय को देखकर स्थानीय गाइड से आदिवासी परिवारों के जनजीवन, रीति-रिवाज और संस्कृति के बारे में जान सकेंगे। पर्यटन विकास समिति खोखरा ने संग्रहालय को देखने के लिए 10 रुपए टिकट तय की है। टिकट बिक्री से मिलने वाली राशि संग्रहालय की देखरेख में खर्च की जाती है। संग्रहालय में 30 वर्ष पुराने 15 से अधिक प्रकार के अनाज को डिब्बों में संजोकर कर रखा गया है। संग्रहालय में दीवार में पोस्टर लगाया गया है जिसमें संग्रहित किए गए किस अनाज में कितना पोषक तत्व मिलते हैं, यह लिखा गया है।

### संग्रहालय में ये अनाज

ग्राम सुधार समिति के अंगिरा प्रसाद बताते हैं कि श्री अन्न संग्रहालय में कोदो, आमागोद, डडगी, लेदरी, कुटकी की मेझरी, अटकी, मेढ़ों, गुड़रू, समा, रागी, फाग, देसी ज्वार, झलरी, देसी मक्का, पीला व सफेद बाजरा शामिल है। इसके साथ ही कोदो व कुटकी और ज्वार का पौधा भी सुखाकर रखा गया है।

### यह है अन्न प्रसंस्करण यंत्र

श्री अन्न प्रसंस्करण यंत्र में ऐसे यंत्र को इकट्ठा किया गया है जो अब विलुप्त हो गए हैं। आदिवासी क्षेत्र की महिलाएं अब भी इन यंत्रों का उपयोग करती हैं। प्रसंस्करण यंत्र में देशी चकरा (मिट्टी), काड़ी, सूपा, मूसल, छोटी चकरी (पत्थर) हैं। वर्षों पुराने लकड़ी से बने हल, जुआ, नाधा, बांस टोपी, पैनारी, गेराई, खोथा, अखैनी, झेपना, बांस पैइला, कुरई, पैइला, कुरआ, खोमरी, मजुराला, हंसिया, खुरपी, कुदाल रखा गया है।

- श्री अन्न संग्रहालय प्रदेश ही नहीं, देश का इकलौता संग्रहालय है। यहां 15 प्रजाति के अनाज, कृषि यंत्र, श्री अन्न प्रसंस्करण को रखा गया है।

**-श्रेयस गोखले, नोडल अधिकारी जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद**

- यहां मिट्टी, लकड़ी और बांस की बने यंत्र रखे गए हैं। पर्यटक इसे देखकर ग्रामीण जीवन को बारीकी से समझ सकेंगे।

**-हिमांशु तिवारी, कार्यपालन यंत्री आरईएस**

### -जहां खड़े होंगे वहीं का पता चलेगा रेट

## अब जमीन की कीमत बताएगा मोबाइल ऐप

भोपाल। जागत गांव हमार

अगर व्यक्ति कहीं कोई जमीन खरीदना चाहता है, तो उसे यह जानने में बहुत परेशानी होती है कि वहां का वास्तविक दाम क्या है, इस समस्या को दूर करने के लिए जल्द ही ऐसा मोबाइल ऐप आ रहा है, जिसके माध्यम से आपको उस जमीन का दाम पता चल जाएगा जिस जमीन पर आप खड़े हैं। नए वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से रजिस्ट्री में पारदर्शिता और सहूलियत और बढ़ जाएगी। तब तक संपदा-टू का ट्रायल पंजीयन कार्यालयों में शुरू हो जाएगा। जिले में करीब सात लाख प्रॉपर्टी में से 90 फीसदी की आईडी बन गयी है। जिसमें प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी, कॉर्नर की जमीन है या फ्लैट है, ड्यूप्लेक्स, मकान या खाली प्लॉट है जैसी जानकारियां दर्ज हो गई हैं। रजिस्ट्री के दौरान प्रॉपर्टी की आइडी डालते ही जमीन या प्रापर्टी की सही जानकारी सामने आ जाएगी।

### एक अप्रैल से लागू होगी व्यवस्था

देश की पहली गूगल ऐप आधारित कलेक्टर गाइड लाइन का काम भी पंजीयन विभाग ने लगभग पूरा कर लिया है। इसे भी नए वित्तीय वर्ष में एक अप्रैल से लागू करने की पूरी तैयारी है। इस ऐप की मदद से किसी भी लोकेशन पर खड़े होकर वहां के रेट की जानकारी मिल जाएगी। कलेक्टर गाइडलाइन में जमीन की दरों की फोन पर ही ऐप की मदद से जानकारी मिल जाएगी। पॉलीगोन ड्रॉ होने से जिले में लोकेशन की संख्या चार हजार से कम हो गई है।

### शहरों में हर पशु को माइक्रो चिप, टैग, ब्रांडिंग कोड दिया जाएगा

### सरकार ने दिखाई सख्ती, अब आवारा छोड़ा तो देना होगा जुर्माना

## प्रदेश में कुत्ते, बिल्ली, गाय-भैंस का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अब कुत्ते, बिल्ली, गाय, बैल, भैंस और अन्य पशु पालने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए अलग-अलग सालाना शुल्क भी देना होगा। रजिस्ट्रेशन के साथ ही पशु का पहचान चिन्ह जारी किया जाएगा। वहीं, यदि पशु को आवारा छोड़ा तो नोटिस पर जुर्माना देना होगा। नगरीय विकास और आवास विभाग ने यह व्यवस्था मध्यप्रदेश नगरपालिका (रजिस्ट्रीकरण तथा आवारा पशुओं का नियंत्रण) नियम 2023 में की है। नियमों में कहा गया है कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले हर पशु को माइक्रो चिप, टैग अथवा किसी अन्य संसाधन से एक ब्रांडिंग कोड दिया जाएगा। इसमें पशुओं की श्रेणी में श्वान, बैल, घोड़ा, सुअर, ऊंट, खच्चर, बकरी, भेड़ या अन्य पशु शामिल हो सकते हैं। नियम के अनुसार एक साल बाद रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन शुल्क के 10 प्रतिशत की दर से पैनाल्टी लगेगी।

**रजिस्ट्रेशन शुल्क 50 से 200 रुपए**

विभाग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पशु मालिक को तीन महीने में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कुत्ते के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 150 रुपए और वार्षिक नवीनीकरण शुल्क 50 रुपए, गाय,बैल के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 200 रुपए और वार्षिक नवीनीकरण शुल्क 100 रुपए तथा अन्य पशु के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 50 रुपए और वार्षिक रजिस्ट्रेशन शुल्क 50 रुपए लगेगा। रजिस्ट्रेशन कराते समय पशु के पानी, प्रकाश, रखने की जगह और उसके मल निष्कासन की व्यवस्था के बारे में जानकारी देनी होगी।

**रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर पैनाल्टी**

विभाग के अनुसार पशु मालिक के तय समयसीमा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क के दस गुना पैनाल्टी का प्रावधान होगा। पशु मालिक को रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान पशु चिकित्सक का सर्टिफिकेट देना होगा। इसमें बताना होगा कि पशु को कोई संक्रामक रोग नहीं है। आवारा घुमने वाले पशुओं को कांजी हाउस में रखा जाएगा। इसके बाद पशु मालिक को नोटिस जारी किया जाएगा और पेनाल्टी लगाई जाएगी।

-भोपाल आईआईएसईआर के वैज्ञानिकों ने किया दावा

# देशी गाय की नस्लों में प्रजनन सुधार

भोपाल। जागत गांव हमार

देशी भारतीय गायों में विशेष क्षमताएं होती हैं, जो उन्हें कठिन परिस्थितियों से अनुकूलन स्थापित करने में मदद करती हैं। खराब गुणवत्ता वाले भोजन को पचाने की क्षमता और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी गुण शामिल हैं। भारतीय गाय की देशी नस्लों के जीनोम को अनुक्रमित करने से उनके और अन्य नस्लों के बीच आनुवंशिक अंतर को समझने में मदद मिल सकती है, जो भविष्य के अध्ययनों और आनुवंशिक सुधार के लिए एक मूल्यवान संसाधन साबित हो सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (आईआईएसईआर), भोपाल के शोधकर्ताओं ने भारतीय गाय की चार देशी नस्लों- कासरगोड बौना, कासरगोड कपिला, वेचुर और ओंगोल के आनुवंशिक गठन का सफलतापूर्वक खुलासा किया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस अध्ययन की सहायता से गायों के प्रजनन और प्रबंधन में सुधार के लिए जीनोम संरचना का उपयोग किया जा सकता है, जिससे भारतीय मवेशी उद्योग में उत्पादकता और स्थिरता में वृद्धि हो सकती है।

**मुश्किल था समझना**- पिछले अध्ययनों ने भारतीय गायों के कई लक्षणों को रेखांकित किया है और पता लगाने का प्रयास किया है कि देशी गाय गर्म मौसम में अपने आकार और दूध की गुणवत्ता को कैसे बनाए रखती हैं। इस अध्ययन में शामिल भारतीय गाय की नस्लों का पूरा जीनोम पहले ज्ञात नहीं था, इसलिए यह समझना मुश्किल था कि उनमें कौन-सी आनुवंशिक विशिष्टताएं होती हैं।

## जीन के विशिष्ट सेट की पहचान

आईआईएसईआर, भोपाल के जैविक विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रो. डॉ विनीत के शर्मा का कहना है कि हमने गाय की देशी नस्लों में जीन के एक विशिष्ट सेट की पहचान की है, जिनमें पश्चिमी मवेशी प्रजातियों के जीन्स की तुलना में अनुक्रमिक और संरचनात्मक भिन्नता देखी गई है। यह जानकारी इस बात की बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है कि भारतीय नस्ल की गाय उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों के साथ अनुकूलन कैसे स्थापित करती है। जीनोम अनुक्रमण, इन देशी नस्लों की आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने में मदद कर सकता है, जो गायों की स्वस्थ और लचीली आबादी को बनाए रखने के लिए अहम है।

## नमूने केरल से संग्रह किए

आईआईएसईआर, भोपाल के शोधकर्ताओं ने भारतीय देशी गाय नस्लों - कासरगोड बौना, कासरगोड कपिला, वेचुर और ओंगोल के जीनोम को पढ़ने और समझने के लिए उच्च-थ्रूपुट अनुक्रमण तकनीकों का उपयोग किया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि ये गायें भारतीय जलवायु परिस्थितियों के साथ कैसे अनुकूलन स्थापित करती हैं। इस अध्ययन के लिए नमूने कासरगोड ड्वार्फ कंजर्वेशन सोसाइटी की मदद से केरल स्थित कपिला गौशाला से संग्रह किए गए हैं।

## बोस इंडिकस एक घरेलू मवेशी प्रजाति

अध्ययन की एक और उपलब्धि दुनिया की सबसे छोटी गाय की नस्ल वेचूर का ड्राफ्ट जीनोम असेंबली है। शोधकर्ताओं ने उन जीन्स की भी पहचान की है, जो बौने और गैर-बौने बोस इंडिकस मवेशियों की नस्लों में अनुक्रमिक भिन्नता के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। बोस इंडिकस एक घरेलू मवेशी प्रजाति है, जिसकी भारत में कई स्वदेशी नस्लें पायी जाती हैं। यह डेयरी, भारवहन और अन्य घरेलू गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन, इस प्रजाति की नस्लों के गठन में विशिष्ट अंतर पाए जाते हैं। इन गाय नस्लों के जीनोम अनुक्रम उपलब्ध नहीं थे। इसलिए, शोधकर्ताओं ने बोस इंडिकस नस्ल की इन चार गाय प्रजातियों के ड्राफ्ट जीनोम असेंबली के निर्माण के लिए पूरे जीनोम अनुक्रमण का खुलासा किया है।

## बीमारियों से लड़ने की भी क्षमता

जीन नामक छोटी इकाइयों से बनी संरचना जीनोम कहलाती है, जिसमें जीवों के बढ़ने, उनके विकसित होने और ठीक से काम करने के लिए आवश्यक जानकारी दर्ज रहती है। जिस तरह एक इमारत के लिए एक ब्लूप्रिंट में यह जानकारी होती है कि इसे कैसे बनाया जाए, जीनोम में वह सभी जानकारी होती है, जो किसी जीव को जीवित रहने के लिए जरूरी है। जीनोम को समझकर, वैज्ञानिक जीवों अथवा पौधों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारियां बीमारियों से लड़ने और पौधों तथा मवेशियों की नस्लों में सुधार में भूमिका निभाती हैं।

-मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को दिया 78 करोड़ का बोनस

# किसानों के कर्ज का पूरा ब्याज भरेगी मप्र सरकार

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनादौन में लघु वनोपज सहकारी समिति की क्षमता वृद्धि के लिए हुए प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम में 13 वन-मंडलों के प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के तेंदूपत्ता संग्राहकों को 78 करोड़ की बोनस राशि वितरित की। साथ ही विभिन्न विभागों के 298 करोड़ 49 लाख लागत के 48 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया। मुख्यमंत्री ने लघु वनोपज संघ द्वारा निर्मित महुआ प्राश की लॉचिंग भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन उपज में आश्रित जनजातीय भाई-बहिनों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राज्य सरकार जनजातीय बंधुओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिए लगातार प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्ज न चुका पाने के कारण डिफाल्टर हुए किसानों का पूरा ब्याज सरकार भरेगी तथा किसानों को बिना ब्याज के कर्ज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा बंद की गई सभी योजनाएं पुन: चालू कर दी गई हैं।

## हितों के संरक्षण करेगा पेसा नियम

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिसूचित क्षेत्रों में पेसा नियम के लागू हो जाने से जनजातीय भाई-बहनों को काफी सहूलियत होगी। उनके हितों के संरक्षण के लिए पेसा नियम लागू किया गया है। अब तेंदूपत्ता तोड़ने की जिम्मेदारी ग्रामसभा निभाएगी। इस कार्य के लिए तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनकी मजदूरी राज्य सरकार देगी। वनोपज जैसे हर्रा, बहेड़ा, सालबीज, आंवला आदि का संग्रहण कर इन उत्पादों को बेचने की आजादी जनजातीय भाई-बहनों के पास होगी। इससे गांव का पैसा गाँव में ही आएगा।

## भूमिहीनों को मिलेगा आवासीय भूमि का पट्टा

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में कोई भी व्यक्ति बिना आवासीय भूमि के नहीं रहेगा। सभी को मुख्यमंत्री भू-आवासीय अधिकार योजना से आवासीय भूमि के पट्टे दिए जाएंगे।

## हितग्राहियों को बांटे गए हितलाभ

**मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया। उन्होंने तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि के वितरण के साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, लाड़ली लक्ष्मी बालिकाओं के प्रमाण-पत्र, आजीविका मिशन के महिला स्व-सहायता समूहों को अनुदान राशि के हितलाभ बांटे।**

-बीते वर्ष दलहनी फसलों का रकबा 48 हजार हेक्टेयर था

## -नर्मदापुरम में इस वर्ष रकबा 65 हजार हेक्टेयर हुआ

# मप्र-राजस्थान, महाराष्ट्र जा रही पिपरिया की दाल

नर्मदांचल। जागत गांव हमार

खाद्यान्न के साथ ही दलहनी फसलों की ओर नर्मदांचल के किसानों का रुझान तेज हुआ है। नर्मदापुरम जिले की पिपरिया की तुअर की दाल की मांग तो राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी होती है। यहां के जलवायु और दालों के स्वाद के कारण जो भी एक बार पिपरिया की दाल का स्वाद चखता है। उसका मुरीद हो जाता है। इसी कारण पिपरिया में तीनों दाल मिले सफल हो गई हैं। शासन के द्वारा भी दलहनी फसलों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा था। कृषि विभाग ने भी जोर मारा इस कारण नर्मदापुरम जिले व संभाग में दलहनी फसलों का रकबा बढ़ता जा रहा है। जहां बीते वर्ष नर्मदापुरम जिले में दलहनी फसलों का रकबा 48 हजार हेक्टेयर में था। वह इस वर्ष बढ़कर 65 हजार हो गया है। जो 17 हजार हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं नर्मदापुरम संभाग में पूर्व में 2 लाख हेक्टेयर में दलहनी फसलें थी इस वर्ष 28 हजार बढ़कर 2 लाख 28 हजार हेक्टेयर में दलहनी फसलें लगाई गई है।

किसान उदय पांडेय का कहना है कि दलहनी फसलों में कुछ जोखिम रहता है। इसमें इल्ली सहित अन्य कीटों का खतरा बना रहता है। इस कारण पहले कम मात्रा में दलहनी फसलें बोई जाती थी। अब आधुनिक समय में अनेक संसाधन उपलब्ध होने से दलहनी फसलों की ओर किसानों का रूख बढ़ता जा रहा है। अनेक तरह के कीटनाशक तथा उपजाऊ बीज आने से दलहनी फसलों से मुनाफा हो रहा है। इसी कारण आने वाले समय में किसानों का रुझान दलहनी फसलों की ओर तेजी से बढ़ेगा।

## मूंग की खेती में अव्वल

ग्रीष्म कालीन मूंग की खेती में जिला प्रदेश ही नहीं देश में अव्वल बना हुआ है। बीते चार वर्षों से लगातार मूंग की पैदावार बढ़ती जा रही है। बीते वर्ष ही 2 लाख 8 हजार हेक्टेयर में मूंग की खेती हुई है। जिससे किसानों को 10 अरब रुपए प्रति वर्ष का मुनाफा हो रहा है।

- किसान तो दलहनी फसलों की ओर बढ़ रहे हैं। उनको उत्तम क्वालिटी के बीज तथा फसलों में रोग लगने पर तुरंत उपाय बताने के साथ उन्हें कीट नाशक दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं तो जिले में और अधिक तेजी से दालों की खेती बढ़ने की प्रबल संभावना है।

**किशोर उमरे**, कृषि विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी

## -60 बीघा में गेहूं उगाया तो लोगों ने कहा पागल, अब वही किसान सीखने आ रहे तकनीकी

# मां ने सिखाई जैविक खेती शिवराज ने दिया अवॉर्ड

धार। जागत गांव हमार

मेरी मां अनपढ़ थीं, लेकिन वो रासायनिक खेती के सख्त खिलाफ थी। जब मैं 12 साल का हुआ तो पिता का निधन हो गया। हमारी जीविका का साधन केवल हमारे खेत थे। मैं मां के साथ खेत में जाता था। उस वक्त हमारे पड़ोस के खेत वाले फसल बढ़ाने के लिए रासायनिक चीजों का जमकर उपयोग करते थे, तब मेरी मां देसी तरीकों पर फोकस करती थीं। जैविक खेती को लेकर जो दीवानगी है, वो मेरी मां ने ही मुझे दी है। ये कहना है धार जिले के ग्राम लबरावदा के किसान नरेंद्र सिंह राठौर का। ये वो ही नरेंद्र है, जिन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैविक खेती करने और उसे बढ़ावा देने के लिए उत्तम किसान अवॉर्ड दिया है। किसान नरेंद्र गाय पर आधारित प्राकृतिक खेती कर उन्नत किसान की श्रेणी में आए हैं। वे फसलों में डाली जाने वाली खाद को घर और खेत पर ही तैयार कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने गाय को अपना मुख्य स्त्रोत बनाया है। स्वदेशी खेती को पुन: स्थापित करने के उद्देश्य से किसान खाद का तरल पदार्थ तैयार कर उसका खेतों में छिडकाव कर रहे हैं। इससे फसलों की गुणवत्ता में सुधार आने के साथ ही केमिकल रहित उपज तैयार हो रही है। जैविक खाद को अपनी खेती तक पहुंचाने के शुरुआती दौर में किसान को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन नरेंद्र ने तीन साल के संघर्ष के बाद अब इसे लाभ का धंधा बनाते हुए जैविक खाद का उपयोग कर एक मिसाल पेश की है।

### पहले से तैयार होते हैं ग्राहक

नरेंद्र बताते हैं कि उनके खेतों में 100 प्रतिशत जैविक खेती होती है। वो जो भी उगाते हैं, ऑर्गेनिक होने के कारण उसके ग्राहक पहले से तैयार होते हैं। रासायनिक खेतों में निश्चित तौर पर ज्यादा फसल होती है, लेकिन उसके दाम इतने नहीं होते, जितने हमारे खेतों में उगे गेहूं के होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक बीघा जमीन में रसायन का उपयोग करने पर 15 से 20 बीघा उत्पादन होता है। उसका दाम दो हजार रुपए क्विंटल तक होता है। वहीं, एक बीघा के खेत में 8 से 10 क्विंटल गेहूं होता है, लेकिन इसका दाम पांच से छह हजार रुपए क्विंटल होता है। भले ही उत्पादन कम हो, दाम ज्यादा होने से फायदा मिलता है।

### एक दिन की ट्रेनिंग में बना देते हैं जैविक किसान

नरेंद्र किसानों को मुफ्त में जैविक खेती करने के तरीके सिखाते हैं। आए दिन नरेंद्र से जैविक खेती सीखने के लिए किसान पहुंचते हैं। नरेंद्र के पास ट्राइबल एरिया और दूसरे स्टेट के किसान ज्यादा होते हैं। नरेंद्र बताते हैं कि हम बंद कमरे में ट्रेनिंग नहीं देते, साथी किसानों को अपने खेत में ले जाते हैं और सीधे प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि कैसे जैविक खाद बनाना है। कैसे मिक्चर बनाना है, कितना बनाना है।

### पहले कियान मारेत थे ताना

नरेंद्र कहते हैं कि जब मैंने 60 बीघा के खेत में जैविक खेती शुरू की तो लोग कहते थे, ये पागल हो गया है। भला केमिकल के बिना भी फसल होगी। इसकी फसल तो कीड़े खा जाएंगे, फिर इसे अकल आएगी। अगर ये नहीं सुधरा तो इसकी जमीन बिक जाएगी। शुरुआती एक दो साल में विफलता भी हाथ आई तो लोग मुंह पर ताना मारकर चले जाते थे, जब मुझे इस जैविक खेती से फायदा होने लगा, तो वही लोग यह तकनीक सीखने मेरे पास आने लगे।

### गौमूत्र से बनाते हैं कीटनाशक

कीट नियंत्रण के लिए भी नरेंद्र जैविक चीजों पर ही निर्भर हैं, कीटों से बचाव के लिए नरेंद्र गौमूत्र, छाछ और नीम के अर्क का उपयोग कर स्प्रे खेत में करते हैं। इस तरह से वे जैविक घोल तैयार करके कीटनाशकों के आक्रमणों का मुकाबला करते हैं। 10 साल से लगातार अपने खेत में रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करने से उन्हें जैविक खेती के संबंध में रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो चुका है। ऐसा करने वाले वे चुनिंदा किसानों में से एक हैं।

### राजीव दीक्षित के वीडियो की ली थी मदद

नरेंद्र बताते हैं कि जब मैंने तय कर लिया था कि पर्यावरण को बिगाड़ने वाले केमिकल अपने खेत में नहीं डालूंगा तो स्वदेशी खाद और कीटनाशक बनाने के लिए मैंने यूट्यूब पर सर्च करना शुरू किया। मुझे याद है पहली बार मैंने पतंजलि के राजीव दीक्षित की वीडियो देखे थे, फिर उनकी किताब पढ़ने लगा। तब मैंने सीखा था कि जैविक खाद को तैयार करने के लिए गायब का गोबर, गाय का गौमूत्र, बड़ के पेड़ के नीचे की मिटटी, बेसन और गुड का उपयोग करके तरल पदार्थ खाद का बनाया जा सकता है। एक एकड़ के लिए 200 लीटर तरल पदार्थ तैयार किया जाता है।

### दक्षिण भारत के लिए बने किसान मित्र

नरेंद्र सिंह राठौर पिछले एक दशक से जैविक खेती करते आ रहे हैं। जैविक खेती के लिए उन्हें उत्तम कृषक का अवॉर्ड मिल चुका है। विपरीत परिस्थितियों के बाद भी हार नहीं मानी। उसका नतीजा यह कि उन्हें गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ शहरों में किसान मित्र कहा जाने लगा है। आज नरेंद्र एक उन्नत कृषक हैं। आज वे विविधता भरी खेती कर रहे हैं, जिसमें गेहूं, चने से लेकर वे करीब 14 तरह की अलग-अलग उद्यानिकी और अनाज की फसल लेते हैं।

### पोषक तत्वों के कारण गुजरात जा रहा गेहूं

नरेंद्र के अनुसार जैविक खाद का उपयोग करने के कारण फसलों का उत्पादन भी बेहतर होता है। हमारे खेत में गेहूं कि देसी किस्म बंशी का उपयोग किया जाता है। इसमें 15 से 20 प्रतिशत अधिक प्रोटीन होता है। इस गेहूं की रोटी खाने से लोगों को पेट में होने वाले बीमारियों से निजात मिलती है। यह जबरदस्त पाचक होता है। यही कारण है कि इस गेहूं की फसल एडवांस में ही बिक जाती है। बंशी किस्म का गेहूं करीब 5 हजार रुपए प्रति क्विंटल और शरबती 6 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक दाम मिल रहा है। इसे इंदौर, अहमदाबाद, चेन्नई, कोयम्बतूर तक भेजा जा रहा है।

### जल संग्रहण के साथ केंचुआ खाद को बढ़ावा

नरेंद्र ने बताया कि उनके द्वारा खेत के तालाब में एक विशेष प्रयोग किया गया है। इसके तहत खेत में तालाब तो बनाया, जिससे कि पानी संग्रहित किया जा सके। तालाब के आसपास करीब 35 नीम के पेड़ भी लगा दिए हैं। इन पेड़ों के कारण तालाब में वाष्पीकरण नहीं होता है। ड्रिप सिंचाई से इस तालाब का पानी खेतों में पहुंचाता है। इससे कम पानी में अच्छी फसल होती है। लगातार 10 वर्ष में अपने खेत की मिट्टी को नरेंद्र ने उस उच्च स्तर पर ला दिया है कि महज दो से तीन इंच की खुदाई करने पर केंचुए बहुत आसानी से आ जाते हैं। ये वो ही केंचुए है, जो भूमि को उर्वरक बनाते हैं। आमतौर पर किसानों के खेतों से केंचुए समाप्त हो गए हैं, लेकिन नरेंद्र के खेतों में यह खूब पनप रहे हैं।

### वाइस प्रिंसिपल से किसान बनने की कहानी

## जैविक खेती से सालान कमा रहे 15 लाख रुपए

**बुरहानपुर।** कैंसर के डर ने एक वाइस प्रिंसिपल और चार्टर्ड अकाउंटेंट को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत छोटे पैमाने पर की, लेकिन अब 18 एकड़ में अलग-अलग फसलें उगा रहा है। इनमें शिमला मिर्च, तरबूज, खरबूज, टमाटर, लौकी, बैंगन आदि शामिल हैं। इस बार उन्होंने एक एकड़ में शिमला मिर्च लगाई है। वह इसे बुरहानपुर, इंदौर के अलावा महाराष्ट्र के जलगांव में बेचते हैं। हर साल करीब 15 लाख रुपए का मुनाफा कमाते हैं। हम बात कर रहे हैं बुरहानपुर जिले की नेपानगर तहसील के किसान गोपाल राठौड़ की। ग्राम अंबाड़ा के रहने वाले गोपाल कॉमर्स से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह महाराष्ट्र के प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल बन गए। इसी बीच, उन्होंने खेती करने का मन बनाया। पहले केमिकल फर्टिलाइजर और रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कर खेती करते थे, लेकिन जीवन में ऐसा मोड आया, जब उनके एक रिश्तेदार की तबीयत खराब हुई। उनको मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पता चला कि उनको कैंसर है। उनकी तीमारदारी के लिए गोपाल टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल में रहे। वहां कुछ ऐसी सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में आए, जिन्होंने बताया कि केमिकलयुक्त खेती से कैंसर का खतरा रहता है। उनकी आंखें खुली और उन्होंने जैविक खेती करने का मन बनाया।

### पहली बार कम, बाद में बढ़ा उत्पाद

गोपाल राठौड़ की मानें तो शुरुआती चार-पांच साल में जैविक खेती से कम उत्पादन हुआ। बाजार में उसका उचित मूल्य भी नहीं मिल पाया, तभी वॉट्सएप ग्रुप बनाया। लोगों को इससे जोड़कर जैविक खेती के प्रति जागरूक करने लगे। इसके बाद लोगों ने जैविक के प्रति रुचि दिखाई। अपने ऑर्गेनिक उत्पाद के थोड़े से प्रचार से बाजार में भी अच्छे दाम मिलने लगे।

### आधा एकड़ में पॉली हाउस

किसान गोपाल राठौड़ ने दो साल पहले करीब 12 लाख रुपए खर्च कर पॉली हाउस बनाया। इसमें जैविक तरीके से सब्जी फसल शिमला मिर्च और टमाटर की खेती की। पॉली हाउस में सब्जियों के लिए बेड बनवाया। सिंचाई के लिए ड्रिप मल्च बिछाकर कुछ दूरी पर शिमला मिर्च के बीज की बोवनी की। पिछले साल 60 टन शिमला मिर्च उत्पादित की। इस बार एक एकड़ में शिमला मिर्च लगाई, जबकि अन्य में दूसरी सब्जियां लगाई। मौसम के हिसाब से फ्रूट्स लगाते हैं।

### ऐसे करते हैं मार्केटिंग

किसान गोपाल एक वॉट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं। ऑर्डर के हिसाब से लोगों को घर तक जैविक सब्जियां पहुंचाते हैं। खास है कि इससे गोपाल को बाजार से ज्यादा दाम भी मिलते हैं। गोपाल के अनुसार एक एकड़ के खेत में एक लाख रुपए खर्च आता है। शुद्ध मुनाफा हर साल 15 लाख रुपए हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका पॉली हाउस निभा रहा है, जिसके माध्यम से गोपाल बेहतर शिमला मिर्च, टमाटर का उत्पादन कर रहे हैं।

### खेती के लिए छोड़ी नौकरी

किसान गोपाल ने एमकॉम, सीए किया। नौकरी की। सात साल एग्रीकल्चर कॉलेज महाराष्ट्र में वाइस प्रिंसिपल की नौकरी की। काम करते समय देखा कि किस तरह प्लॉट तैयार होते हैं। कंपनियों के सीड प्रोडक्शन होते हैं। वहां से खेती करने का विचार मन में आया। तब हालात ठीक नहीं थे, इसलिए छोटे स्तर पर खेती स्टार्ट की। सात साल जॉब कर फिर नौकरी छोड़कर यहां खेती करना शुरू किया

### फैमिली पैक बनाकर देते हैं

किसान राठौड़ फैमिली पैक बनाकर देते हैं, जिसमें डेली यूज की सब्जियां, फल शामिल होते हैं। वह सब्जी, भाजी फ्रूट और बैंगन, टमाटर, गिलकी, करेला, लौकी, शिमला मिर्च, हरी मिर्च आदि फैमिली पैक बनाकर देते हैं। सीजन के हिसाब से फ्रूट भी चेंज करते हैं।

# शिवराज के पौध-रोपण की गूंज लोकल से ग्लोबल स्तर तक

**संदीप कपूर**

**जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव के इस दौर में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान द्वारा प्रतिदिन पौध-रोपण से देश-विदेश में मध्यप्रदेश का नाम पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध एक ब्राण्ड के रूप में स्थापित हुआ है। देश-विदेश में जब संगोष्ठियों, सेमीनारों और पर्यावरणीय विमर्श में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों की रोकथाम पर महज अकादमिक चर्चा हो रही है, तब शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में व्यक्तिगत स्तर पर कर्म करने का प्रण लिया। यह प्रण था प्रतिदिन स्वयं पौधा लगाने का और पौधा लगाने के प्रतिदिन के उपक्रम में लोगों को जोड़ने का।**

आज से दो साल पहले मुख्यमंत्री चौहान ने माँ नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में 19 फरवरी 2021 को नर्मदा जयंती के अवसर पर प्रतिदिन पौधा लगाने की जो शुरूआत की उसे वे दो वर्ष बाद भी निरंतर रखे हुए है। सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे मौसम के बदलाव हों या स्वयं के स्वास्थ्य की समस्याएँ, या फिर मुख्यमंत्री के दायित्व निर्वहन की व्यस्तताएँ और प्रदेश व प्रदेश के बाहर के प्रवासों की उलझनें, कोई भी स्थिति उन्हें प्रतिदिन पौध-रोपण के अपने प्रण से डिगा नहीं पाई। चौहान ने इन दो वर्षों के 730 दिनों में लगभग 2200 पौधे लगाए। पौधे लगाने की गतिविधि का विस्तार भोपाल सहित प्रदेश के कई कस्बों और शहरों से लेकर देश के 12 राज्यों तक हुआ। अब स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री चौहान के साथ प्रतिदिन कई सामाजिक संगठन और व्यक्ति, स्व-प्रेरणा से पौध-रोपण कर रहे हैं। यही वजह है कि बिन्दु से आरंभ हुआ सामाजिक सरोकार का यह प्रयास सिंधु बनने की ओर निरंतर अग्रसर है।

मुख्यमंत्री चौहान, मुख्यमंत्री होने के साथ-साथ जन-जन के सर्वमान्य नेता, प्रदेश के बच्चों के मामा, बहनों के भाई और प्रदेश के परिवेश में रचे-बसे ?जननायक हैं। प्रदेशवासियों पर उनकी हर अपील का आत्मीय प्रभाव होता है। चौहान ने पौध-रोपण के अपने प्रण से जन-जन को जोड़ने के लिए लोगों को अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों जन्मदिवस, विवाह वर्षगांठ तथा अपने परिजनों की स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उनकी पुण्य-तिथि पर पौधे लगाने का आहवान किया है। उनके आहवान के परिणामस्वरूप राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में पौध-रोपण की गतिविधि को विस्तार मिला। देश-दुनिया जब कोरोना से प्रभावित थी तब भी उस काल में कोरोना से बचाव की सावधानियों के साथ पौध-रोपण जारी रहा। कोरोना के नियंत्रण में आने के साथ ही, जनवरी 2022 से श्यामला हिल्स स्थित स्मार्ट सिटी उद्यान में मुख्यमंत्री के साथ अपने जन्मदिवस, विवाह वर्षगांठ या परिजनों की स्मृति में पौधे लगाने के लिए आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। जनवरी 2022 से अब तक लगभग 1600 से अधिक व्यक्तियों ने उनके साथ पौधे लगाए। इस तरह चौहान का व्यक्तिगत प्रण, समाज का प्रण बन गया।

पर्यावरण संरक्षण के पावन कार्य में जन-सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश में मुख्यमंत्री चौहान ने एक और नई पहल की है। यह पहल है विश्व पर्यावरण दिवस 05 जून 2021 से आरंभ किया गया प्रदेशव्यापी अंकुर कार्यक्रम। कार्यक्रम की अनूठी बात यह है कि लोग पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण के महायज्ञ में अपने योगदान को डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित रख सकते है। इसके लिए वायुदूत एप पर रजिस्ट्रेशन कराकर स्वयं के द्वारा लगाए गए पौधे की फोटो अपलोड करने की व्यवस्था है। पौधा लगाने के बाद उसकी देख-रेख की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभागियों के लिए निश्चित समयावधि के बाद पुन: फोटो अपलोड करने के साथ ही चयनित लोगों को प्राण वायु अवार्ड से सम्मानित करने की व्यवस्था भी है।

मुख्यमंत्री चौहान स्वयं के द्वारा किये गये पौध-रोपण से प्रदेशवासियों को भी इस महत्वपूर्ण और मानवसेवी गतिविधि से जोड़ने में सफल हुए हैं। यही नहीं एक राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं प्रतिदिन पौध-रोपण और फिर उसमें जन-

सहभागिता से देश-विदेश में मध्यप्रदेश, पर्यावरण-संरक्षण के लिए एक संवदेनशील और प्रतिबद्ध ब्राण्ड के रूप में स्थापित हुआ है। चौहान ने प्रत्येक प्रमुख अवसर पर अपने पौध-रोपण के प्रण को पूरी प्रभावशीलता के साथ प्रकट किया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने स्वयं भोपाल के स्मार्ट सिटी उद्यान में बरगद का पौधा लगाया। राज्यपाल मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री चौहान तथा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा भी राष्ट्रपति के साथ पौध-रोपण में शामिल हुए और पीपल तथा कचनार के पौधे लगाए। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु द्वारा मध्यप्रदेश की पावन धरती पर पौध-रोपण के लिए उनका आभार मानते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने कहा था कि इससे हमारे उस अभियान को बल मिला है, जो हर व्यक्ति को महत्वपूर्ण अवसर पर पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है।

हाल ही में मध्यप्रदेश को कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेज़बानी का अवसर प्राप्त हुआ। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जहाँ देश-विदेश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक मध्यप्रदेश में आए, वहीं विदेश मंत्रालय द्वारा इंदौर में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में गुयाना गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफ़ान अली, सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिकाप्रसाद संतोखी तथा विश्व के लगभग सभी प्रमुख देशों में फैले प्रवासी भारतीय, मध्यप्रदेश आये। खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2022 का आयोजन प्रदेश के सात शहरों, जी-20 के कृषि कार्य समूह बैठक का आयोजन इंदौर में और जी-20 के ही थिंक-20 की बैठक भोपाल में हुई। साथ ही भारत सरकार द्वारा वॉटर विज़न समिट और अन्य राष्ट्रीय स्तर की बैठकें प्रदेश में आयोजित की गई। इन आयोजनों में देश-विदेश से आए प्रतिनिधि मंडलों के सदस्य और गणमान्य नागरिकों ने मुख्यमंत्री चौहान की पर्यावरण-संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को देखकर स्वयं आगे आते हुए भोपाल और इंदौर में पौध-रोपण में शामिल हुए। परिणामस्वरूप मुख्यमंत्री चौहान के प्रतिदिन पौध-रोपण के प्रण की गूँज लोकल से कहीं आगे जाकर ग्लोबल स्तर तक हो रही है।

मुख्यमंत्री चौहान के साथ हार्ट फुलनेस संस्थान के वैश्विक अध्यक्ष परम पूज्य दाजी कमलेश पटेल, परम पूज्य सदगुरु जग्गी वासुदेव ने भी पौधे लगाए। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रमों के कार्यकारी निदेशक रहे एरिक सॉल्हिम, साउथ अफ्रीका दूरिज्म की हब प्रमुख सुनेलिस्वा जकाबी, विज्ञापन जगत की जानी-मानी हस्ती पद्मपीयूष पाण्डेय, कश्मीर फाईल्स के निदेशक विवेक अग्निहोत्री, फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार सहित खेल, कला-संस्कृति, शिक्षा जगत और राजनैतिक क्षेत्र के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भी मुख्यमंत्री चौहान के साथ पौधरोपण किया। मुख्यमंत्री चौहान से प्रेरणा लेकर प्रदेश में आओ पेड़ लगाएं-हरा भरा मध्यप्रदेश बनाएं तथा एक पेड़-एक जिन्दगी अभियान संचालित किए गए। मुख्यमंत्री चौहान पौध-रोपण में स्थानीय जलवायु और परिवेश के अनुरूप पौधे लगाने को प्राथमिकता देते हैं। उनका मानना है कि पेड़ मनुष्यों को तो जीवन देते ही हैं। पशु-पक्षी, जीव-जंतु, कीट-पतंगों को भी आश्रय और जीवन प्रदान करते हैं। अमरकंटक में 19 फरवरी 2021 को नर्मदा जयंती पर गुल बकावली और साल का पौधा लगाकर आरंभ अपने प्रण की पूर्ति के उपक्रम में चौहान ने पारिजात, सप्तपर्णी, अशोक, कदम्ब, हरसिंगार, बेल पत्र, मौलश्री, शीशम, मुनगा, करंज, गुलमोहर, कचनार, हर्र, मधुकामिनी, अर्जुन, नीम, आंवला, विलायती इमली, हल्दू, नीला गुलमोहर, बॉटल ब्रश, कपूर आदि के पौधे लगाए हैं।

# राहुल के बिना विपक्षी एकता कांग्रेस को अस्वीकार्य

**कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उसका शीर्ष नेतृत्व, इस बात पर अंतिम फैसला करेगा कि दूसरे विपक्षी दलों के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन किया जाए या चुनाव के बाद गठबंधन किया जाए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 24 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाले कांग्रेस के 85वें पूर्ण सत्र में पार्टी के 15,000 नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें पार्टी के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। हालांकि, पार्टी ने जोर देकर कहा कि वह 2024 के लोकसभा चुनावों में सत्ताधारी बीजेपी को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इसके बिना प्रस्तावित विपक्षी एकता संभव नहीं है।**

पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, कांग्रेस पार्टी की ओर से एक स्पष्ट पहल की जा रही है, कांग्रेस अपनी भूमिका निभाएगी। पूर्ण अधिवेशन के दौरान इस पर चर्चा होगी। स्पष्ट विचार-विमर्श शुरू होगा। पूर्ण सत्र से दिशा मिलेगी। वेणुगोपाल ने ये बातें रायपुर अधिवेशन की तैयारियों के संबंध में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। इसमें जयराम रमेश, पवन बंसल, कुमारी शैलजा और तारिक अनवर सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को यह कहकर विपक्षी एकता के मुद्दे को राजनीतिक केंद्र में वापस ला दिया कि अगली लोकसभा में बीजेपी को 100 से कम सीटों तक सीमित करना संभव है, बशर्ते सभी विपक्षी दल एक साथ आएं। वैसे तो, सभी विपक्षी दलों का बीजेपी विरोधी गठबंधन बनाने की बातचीत पिछले एक साल से चल रही है, लेकिन यह सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई है। नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद पिछले साल सितंबर में अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान ऐसी ही एक पहल की थी। नीतीश कुमार ने अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। इसके तुरंत बाद दो कारणों से उनकी पहल ठप पड़ गई। कांग्रेस पार्टी अपनी महत्वाकांक्षी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हो गई। यह यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई और 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त हुई। कांग्रेस पार्टी द्वारा नीतीश कुमार की पहल को ठंडे बस्ते में डालने का एक दूसरा कारण यह रहा कि उनकी नई दिल्ली यात्रा इन अटकलों के बीच हुई थी कि वे संयुक्त विपक्ष के संभावित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में खुद को पेश करना चाहते हैं। पिछले 14 वर्षों के कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यों को नेहरू-गांधी परिवार के पांचवीं पीढ़ी के नेता राहुल गांधी को देश के संभावित प्रधानमंत्री के रूप में प्रचारित करने तक ही सीमित कर दिया गया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी को 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में संयुक्त

प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया। 2019 में राहुल गांधी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इन दोनों चुनावों में पार्टी ने क्रमशः 44 और 52 सीटें हासिल कीं और अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 2014 में पूर्ण बहुमत हासिल करके और 2019 में अपने प्रदर्शन में सुधार करके केंद्र में गठबंधन सरकारों के 25 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसे भारतीय मतदाताओं द्वारा राहुल गांधी की अस्वीकृति के रूप में देखा गया। हालांकि, 2024 के आम चुनावों में मोदी से मुकाबला के लिए पार्टी किसी और को मौका देने के मूड में नहीं है।

पार्टी ने संसदीय और राज्य चुनावों में बार-बार चुनावी हार के साथ इसकी भारी कीमत चुकाई और केवल तीन राज्यों की सत्ता में सीमित रह गई। इनमें से दो राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान हैं। जहां इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। विपक्ष को एकजुट करने और 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रयास पिछले साल पश्चिम बंगाल के चुनावों के तुरंत बाद शुरू हुआ, जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की।

# एविएशन सेक्टर में आएगा बड़ा बदलाव

इंडियन एविएशन सेक्टर नई ऊंचाइयां छूने की तैयारी में है। इसका आगाज किया है एयर इंडिया ने, एयरबस और बोइंग को 840 विमानों का ऑर्डर देकर। टाटा संस का अमेरिका और फ्रांस की इन कंपनियों के साथ हुआ 85 अरब डॉलर का यह सौदा, एविएशन इंडस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी डील है। आइए, समझते हैं इस डील से क्या बदलाव आएगा भारतीय एविएशन सेक्टर में? यह जो डील हुई है, उससे पांच-सात साल में दुनिया के जितने भी मेजर डेस्टिनेशन हैं, वहां के लिए एयर इंडिया सीधी विमान सेवा शुरू कर पाएगी क्योंकि कंपनी हर रेंज के हवाई जहाज खरीदने जा रही है। एयर इंडिया डीप कमर्शल पार्टनरशिप भी करेगी तमाम पार्टनर्स के साथ, जैसे- सिंगापुर एयरलाइंस और लुफ्थांसा। फिर कंपनी के साथ स्टार एयरलाइंस वाले भी मजबूत करेंगे साझेदारी। इसका असर यह होगा कि आने वाले समय में भारतीय यात्रियों को सुबह 4 बजे की फ्लाइट खाड़ी देशों में जाने के लिए नहीं पकड़नी पड़ेगी और ना ही वहां से ढाई-तीन घंटे की दूसरी फ्लाइट लेनी होगी। एयर इंडिया के साथ इंडिगो भी इस बाजार की दिग्गज खिलाड़ी है। आज की तारीख में इंडिगो करीब 310 प्लेन ऑपरेट कर रही है। उसने 500 हवाई जहाज के और ऑर्डर दे रखे हैं। इन्हें देखकर लगता है कि आने वाले वर्षों में भारत में एविएशन इंडस्ट्री का रंग-रूप पूरी तरह से बदलने वाला है। इंडिया में हमारे पास प्लस पॉइंट है ट्रैफिक। हम लोग ट्रैफिक जेनरेट कर सकते हैं। उसकी वजह से आसपास के हब्स पर जब उतरते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी भारतीय रेलवे स्टेशन पर हैं। भारत का ट्रैफिक फीड होता है वहां, जिससे बड़े हवाई जहाज भरते हैं, जो दुनिया के कोने-कोने में जाते हैं। अब यही भारत में होगा। हालांकि ध्यान रखना चाहिए, इंडियन एयरलाइंस का मतलब यहां उन एयरलाइंस से है, जो वित्तीय रूप से मजबूत हैं। पहले देखा गया कि कुछ एयरलाइंस शुरू हुईं और दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद बंद हो गईं। जेट एयरवेज 26 साल चली, उसके बाद बंद हो गई। अब इसे दूसरे मालिक शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं।

-इंदौर का सीवेज युक्त 250 एमएलडी पानी शिप्रा में मिलता है

# कान्ह नमामि गंगे मिशन में शामिल अब उज्जैन में शिप्रा भी होगी निर्मल

उज्जैन। वंदना बृजेश परमार

केंद्र सरकार ने प्रदूषित कान्ह नदी को 'नमामि गंगे मिशन' में शामिल कर 511 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट स्वीकृत कर दिया है। स्वीकृत राशि से इंदौर में 195 एमएलडी (मिलियन लीटर्स पर-डे) के तीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाए जाएंगे। इन प्लांट में उपचारित पानी आगे जाकर हमेशा की तरह उज्जैन में प्रवाहित शिप्रा में मिलेगा। इससे शिप्रा शुद्धीकरण को भी गति मिलेगी। एसटीपी का निर्माण अगले दो वर्ष में पूर्ण किए जाने का दावा इंदौर नगर निगम ने किया गया है। देश के सबसे स्वच्छ इंदौर का सीवेज युक्त 250 एमएलडी पानी कान्ह नदी के रूप में उज्जैन आकर शिप्रा में मिलता है। इससे शिप्रा का स्वच्छ पानी भी दूषित होता है। ऐसा न हो, इसके लिए बीते ढाई दशक में राज्य और केंद्र की सरकार ने कई प्रयास किए। अरबों रुपए भी खर्चे, बावजूद शिप्रा का जल शुद्ध नहीं हो सका।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में शिप्रा का जल 'डी' ग्रेड का है। इसका साफ मतलब यह है कि शिप्रा का पानी आचमन छोड़ स्नान लायक भी नहीं है। स्नान पर्व, महाकुंभ सिंहस्थ-2028 करीब है, पीने के पानी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में सरकार ने अब ओर अधिक देरी न करके कान्ह को 'नमामि गंगे मिशन' में शामिल कर नए एसटीपी लगाने को 511 करोड़ मंजूर कर दिए हैं। इंदौर नगर निगम रिपोर्ट के अनुसार इस राशि से कबीटखेड़ी में 120 एमएलडी, लक्ष्मीबाई प्रतिमा के समीप 35 एमएलडी और कनाड़िया क्षेत्र में 40 एमएलडी क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। निर्माण पर 244 करोड़ खर्च होंगे।

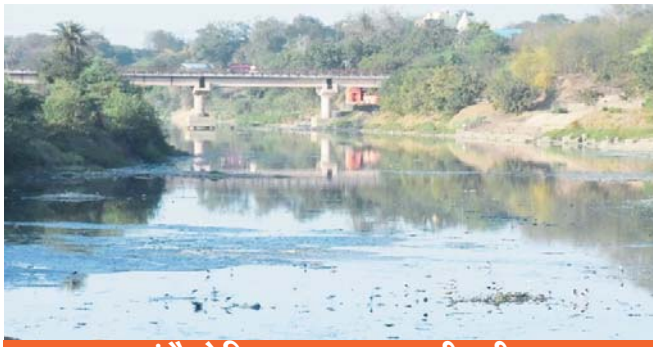

## इंदौर से निकलता 412 एमएलडी पानी

इंदौर शहर से रोज 412 एलएलडी पानी निकलता है। ये पानी विभिन्न नाले-नालियों से गुजरकर 10 विभिन्न एसटीपी पर उपचार के लिए पहुंचता है। यहां से पानी उपचारित कर शिप्रा में मिलने के लिए छोड़ा जाता है। अफसर, मंत्री कई मर्तबा कह चुके हैं कि कान्ह का पानी शिप्रा में मिलने से शिप्रा का जल दूषित होता है। यानी स्पष्ट है कि इंदौर में कान्ह के पानी का सही ढंग से उपचार नहीं हो रहा।

**संसद में उठाया था मुद्दा-** यहां के सांसद अनिल फिरोजिया ने सवा साल पहले लोकसभा में शिप्रा शुद्धिकरण का मुद्दा उठाया था। सदन में कहा था कि इंदौर से निकली कान्ह नदी का दूषित पानी उज्जैन में प्रवाहित शिप्रा नदी में मिल रहा है। इससे शिप्रा का स्वच्छ जल प्रदूषित हो रहा है। ये जल आचमन लायक भी नहीं है। शिप्रा के शुद्धीकरण के लिए ठोस योजना बनाई जानी चाहिए। जितना धार्मिक महत्व गंगा नदी का है, उतना ही शिप्रा नदी का भी है।

### क्लोज डक्ट परियोजना मंजूर

दो महीने पहले शिप्रा शुद्धी के लिए मप्र सरकार 598 करोड़ 66 लाख की क्लोज डक्ट परियोजना को मंजूरी प्रदान कर चुकी है। योजना अंतर्गत कान्ह का दूषित पानी शिप्रा के नहान क्षेत्र में मिलने से रोकने के लिए गोठड़ा गांव में कान्ह पर पांच मीटर ऊंचा स्टापडेम बनाया जाएगा। यहां से कालियादेह महल के आगे तक 16.5 किमी लंबा एवं 4.5 बाय 4.5 मीटर चौड़ा आरसीसी बाक्स बनाकर जमीन पर बिछाया जाएगा। इससे 40 क्यूमेक पानी डायवर्ट किया जा सकेगा। अंतिम 100 मीटर लंबाई में ओपन चैनल का निर्माण किया जाएगा।

### 90 करोड़ की योजना मंजूरी का इंतजार

शिप्रा शुद्धि के लिए उज्जैन नगर निगम की ओर से केंद्र सरकार को भेजी 90 करोड़ रुपए की पियालाखाल, भैरूनाला उन्नयन की परियोजना की स्वीकृति मिलने का अब इंतजार है। परियोजना की कार्य लागत 38 करोड़ और 15 वर्ष तक इसके मैंटेनेंस का अनुमानित खर्च 52 करोड़ रुपए है।

### निर्माण एजेंसी 15 साल करेगी रखरखाव

परियोजना का रखरखाव निर्माण एजेंसी 15 वर्षों तक करेगी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सात वर्ष पहले कान्ह डायवर्शन नाम से कुछ इसी तरह की पाइपलाइन योजना अमल में लाई गई थी। योजना पर 95 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। हालांकि ये योजना पूरी तरह सफल नहीं हुई। कभी पाइपलाइन लीकेज तो कभी ओव्हर फ्लो की वजह से शीतकाल, ग्रीष्मकाल में भी कान्ह का पानी नहान क्षेत्र में मिलता रहा। इसी के फलस्वरूप अब क्लोज डाक्ट परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए ठेकेदार चयन करने को निविदा की कार्रवाई प्रक्रिया में है।

कृषि मंत्री बोले-मप्र में पंजीयन की तारीख 15 दिन बढ़ाई

# चना, मसूर और सरसों का पंजीयन किसान 10 मार्च तक करा सकेंगे

भोपाल। जागत गांव हमार

किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किसानों के हित में सभी निर्णय लिए जाते हैं। किसान पुत्र मुख्यमंत्री ने एक बार फिर किसान हित में निर्णय लेते हुए चना, मसूर, सरसों के पंजीयन की तारीख को 15 दिन बढ़ा दिया है। कृषि मंत्री ने बताया कि किसान चना, मसूर, सरसों की उपज का पंजीयन पोर्टल पर 10 मार्च तक करा सकते हैं। पूर्व में पंजीयन की तारीख 25 फरवरी नियत की गई थी। मंत्री ने कहा कि जिन किसान भाइयों ने अभी तक पोर्टल पर पंजीयन नहीं कराया, उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सभी किसान निर्धारित तिथि तक अपनी उपज का पंजीयन पोर्टल पर करा लें। उनकी उपज का एक-एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा।

### हितग्राहियों को स्वीकृति-पत्र वितरित

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने हरदा के संत रविदास चौक से विकास यात्रा में शामिल हुए। विकास यात्रा के समापन अवसर पर कृषि मंत्री ने नागरिकों को संबोधित करते हुए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कुमारी निवेदिता नायड़े और नित्या प्रजापति को लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रमाण-पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि जल-जीवन मिशन के तहत गांव-गांव में नल जल योजना के माध्यम से घर-घर तक पानी भरपूर मात्रा में पहुंचाया जा रहा है।

### युवाओं को बना रहे आत्मनिर्भर

कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्व-रोजगार योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हमारे युवा, दूसरों को भी रोजगार प्रदाता बनें। मंत्री ने हरदा में पॉलिटेक्निक कॉलेज के ऑडिटोरियम में हितग्राहियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने हरदा में हितग्राहियों को स्व-रोजगार योजनाओं के स्वीकृति-पत्र वितरित किए। मंत्री ने कहा कि सरकार सभी के कल्याण के लिये योजनाएं बना कर क्रियान्वित कर रही है। इससे प्रदेश के किसान, गरीब, महिला और युवाओं के लिए प्रगति के द्वार खुले हैं और सभी के आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

-रंगों का पर्व होली इस बार फूलों से बनने वाले हर्बल रंगों से नहीं महकेगा

# फूल आने के बाद भी वन विभाग की प्राकृतिक कलर बनाने में रुचि नहीं

भोपाल। जागत गांव हमार

रंगों का पर्व होली इस बार फूलों से बनने वाले हर्बल रंगों से नहीं महकेगा। इसमें वन विभाग ने इन रंगों को बनाने में रूचि नहीं लेना सामने आया है। दरअसल इस बार वन विभाग द्वारा प्राकृतिक फूलों से रंग बनाने की कोई तैयारियां दिखाई नहीं दे रही है। इधर, होली का त्योहार मैं कुछ ही दिन शेष है। विभाग के अधिकारियों का मानना है कि रंग बनाने के लिए उपयोग में आने वाले फूल पके नहीं है। इसलिए काम शुरू नहीं हुआ है। जमीनी हकीकत इससे कुछ और है फूल पककर तैयार हो चुका है और जमीन पर गिरने भी लगा है। वन विभाग के सुस्त रवैया से होली की मस्ती के दीवानों को हर्बल रंगों के लिए निराश होना पड़ेगा। गौरतलब है कि पुराने समय में प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुलाब, पलाश, कुसुम, अमलतास आदि फूलों से बनने वाले प्राकृतिक रंगों से यहां के लोग होली खेलते आए हैं। हालांकि विगत कुछ वर्षों से इन प्राकृतिक हर्बल रंगों की जगह केमिकल से बनने वाले रंगों ने ले ली थी, केमिकल के रंगों से होने वाले नुकसान और इंफेक्शन को देखते हुए शासन द्वारा वन विभाग को हर्बल कलर बनाने के लिए आदेशित किया। बड़े पैमाने पर विभाग द्वारा प्रदेश के कई इलाकों में फूलों से प्राकृतिक रंग तैयार भी किए गए थे और बिक्री के लिए इंस्टॉल भी लगे। लेकिन स्थानीय वन विभाग द्वारा न पहले इस कार्य में रुचि दिखाई और न ही अब दिखाई दे रही है।

### फूलों की बहार से महक रहे जंगल

प्रदेश के जंगलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। जिसके चलते प्राकृतिक हर्बल रंग बनाने के लिए उपयोग में आने वाले पलाश, कुसुम, अमलतास आदि के फूल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। फूलों की बहार से मप्र के जंगल महक रहे है। वन परिक्षेत्रों के रास्तों पर फूलों से सजे यह पेड़ प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाते नजर आ रहे हैं। फूल पूरी तरह से पक कर तैयार हो चुका है और अब यह जमीन पर खिरने भी लगे हैं। रंग बनाने का आसान है तरीका प्राकृतिक रंग बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और इसको बनाने के कई तरीके हैं। फूलों को सुखाकर या फूलों को पानी में भिगोकर रखा जाता है, जिसके कारण फूलों का रंग पानी में उतर आता है।

### हर्बल रंग हर मायने में फायदेमंद

दूसरी तरफ फूलों को सुखाकर पानी में उबाला जाता है और उसके बाद इस पानी में पर्याप्त मात्रा में आरारोट मिलाकर रंग तैयार किया जाता है। मूलत: पलाश, खाकरा, केसूड़ी, अमलतास कनेर आदि फूलों का उपयोग किया जाता है। केमिकल रंग त्वचा को रूखा बना देता है इस विषय को लेकर चल चर्म रोग विशेषज्ञ सुमित शर्मा से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि केमिकल रंग त्वचा को रूखा और बेजान बना देते हैं। कई बार देर से निकलने वाले यह रंग खुजली, जलन और इंफेक्शन करते हैं। इनसे दूर ही रहना चाहिए। फूलों से बने प्राकृतिक हर्बल रंग हर मायने में फायदेमंद है।

## केंद्रीय मंत्री के हाथों सचिव नरहरि ने ग्रहण किया अवार्ड

-करवाया गया 30 करोड़ से अधिक का विलंबित भुगतान

# मध्यप्रदेश के एमएसएमई विभाग को केंद्र ने नवाजा

**भोपाल। जागत गांव हमार**

मध्यप्रदेश के खाते में एक और उपलब्धि अर्जित हुई है। केन्द्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के एमएसमएई के विलंबित भुगतानों के निराकरण के लिए सुक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन कॉउन्सिल को स्ट्रांग रिकवरी प्रोसिजर एवं प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए, एमएसईएफसी एक्सिलेंस अवार्ड-2022 प्रदान किया है। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गत दिवस मप्र के एमएसएमई विभाग के सचिव और उद्योग आयुक्त पी. नरहरि को यह प्रतिष्ठापूर्ण अवार्ड प्रदान किया। केन्द्रीय एमएसएमई के अतिरिक्त सचिव डॉ. रजनीश, लघु उद्योग भारती के सदस्य श्री महेश गुप्ता, राजेश कुमार मिश्रा सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे। नरहरि ने बताया कि एक जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 तक कॉउन्सिल की 19 बैठकें हुई, जिसमें कुल 472 प्रकरणों में

सुनवाई की और 303 प्रकरणों में अंतिम निर्णय कर विभागीय पोर्टल में अपलोड किए गए। अवार्ड एवं सुलह के माध्यम से तीस करोड़ 51 लाख 30 हजार 571 रुपए का भुगतान कराया गया। कॉउन्सिल की बैठक प्रत्येक प्रथम एवं तृतीय शुक्रवार को की जाती है और उभय पक्षों को वर्चुअल सुनवाई की सुविधा भी दी जाती है। पी. नरहरि ने बताया कि केन्द्र सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 15 से 23 तक सप्लायर को यह अधिकार होता है कि यदि उसने क्रेता को सामग्री/सेवा प्रदाय की है तो नियत दिनांक से 45 दिवस के पूर्व क्रेता को भुगतान करना आवश्यक है। समयवधि में भुगतान नहीं होता है तो, सप्लायर को अधिनियम अन्तर्गत क्रेता से मूलधन के साथ 3 गुना चक्रवृद्धि मासिक ब्याज पाने का दावा अधिनयम की धारा 18 में कर सकता है।

स्कैन करने पर मिलेगी औषधीय जानकारी

## जीवाजी विवि के पेड़ों पर लगाए बारकोड

**ग्वालियर।** जीवाजी विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग ने लक्ष्मीबाई कन्या छात्रावास में पेड़ों पर बारकोड लगाए हैं। इन बारकोड को स्कैन करने पर पेड़ के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। यह बारकोड छात्रावास में लगे नीम, सिरिस, जामुन, आश, चिरोल, आम, पाम, कटहल, बेल, महारूख, अमरूद, नींबू सहित 40 पेड़ों पर लगाए गए हैं। इस व्यवस्था से विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को बारकोड स्कैन से डाटा एकत्रित करने में सहायता मिलेगी।

छात्रावास की वार्डन डॉ. निमिषा जादौन ने बताया कि यह विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा छात्रावास है, यहां अधिक संख्या में छात्राएं रहती हैं। इस प्रयोग से सभी छात्राओं को काफी लाभ होगा। जीवाजी विश्वविद्यालय के चीफ वार्डन प्रो. केएस ठाकुर ने बताया कि विवि में हुए इस प्रयोग से छात्रों का पर्यावरण के प्रति लगाव और जागरूकता बढ़ेगी। साथ ही बारकोड को स्कैन करने पर यह भी जान सकेंगे कि वह पेड़ कितनी आक्सीजन छोड़ता है और औषधीय गुणों के आधार पर चिकित्सा के क्षेत्र में कितना उपयोगी है।

## 2024 तक हर घर में नल से मिलेगा जल

**भोपाल।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि वर्ष 2024 तक सभी को पक्का आवास मिले, इसके लिए राज्य सरकार तेजी से कार्य कर रही है। वर्ष 2024 तक हर घर में नल से शुद्ध जल मिले, इसके लिए भी जलजीवन मिशन के तहत तीव्र गति से कार्य चल रहा है। शाजापुर जिले में कालीसिंध-नर्मदा लिंक परियोजना से वर्ष 2024 तक अपने हिस्से का पानी मिलने लगेगा। इस पानी का उपयोग सिंचाई एवं पेयजल के लिए किया जाएगा। वर्ष 2024 तक हर घर में नल से जल वितरित होगा। इसके लिए जलजीवन मिशन के तहत तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। यह बात प्रदेश के स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इन्दर सिंह परमार ने आज शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में निकाली गयी विकास यात्रा के दौरान कही।

प्रो. पयासी बोले-बागवानी, दुग्ध उत्पादन, मछली पालन करना होगा

# खेती को लाभ का धंधा बनाने अपनानी होगी समन्वित कृषि

**रीवा।**

कृषि महाविद्यालय रीवा में छह दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय रीवा प्रो. एसके पयासी ने कहा कि खेती को लाभ का धंधा बनाना है तो समन्वित कृषि प्रणाली पद्धति अपनाना होगा जिसमें फसलों के साथ बागवानी, दुग्ध उत्पादन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन आदि विविधाओं का समावेश करना पड़ेगा। छात्र छात्राओं के उद्यमिता एवं व्यक्तित्व विकास के लिए इस कार्यशाला में मधुमक्खी पालन स्वरोजगार के लिए एक उत्तम व्यवसाय, एफपीओ बनाने की प्रक्रिया, स्वरोजगार के लिए बैंक प्रणाली से ऋण एवं क्रेडिट कार्ड लेने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। तकनीकी सत्र में डॉ. आईएम खान, डॉ. एसके त्रिपाठी, डॉ. राजेश तिवारी, डॉ. अखिलेश कुमार, डॉ. प्रदीप मिश्रा, एसएल पटेल, फील्ड ऑफिसर, एसबीआई के साथ एफपीओ गौ फार्मा के डायरेक्टर आशीष मिश्रा ने भाग लिया। संचालन प्रो. आरके तिवारी ने किया।

### अनुभवात्मक कृषि स्वरोजगार का माध्यम

इधर, कृषि कॉलेज रीवा के अधिष्ठाता प्रो. एसके पयासी के मार्गदर्शन में उद्यान विभाग द्वारा बीएससी कृषि चतुर्थ वर्ष के छात्रों द्वारा रोजगार खोजने के बजाय रोजगार देने के संबंध में अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। कार्यक्रम के प्रभारी प्रो. राजेश तिवारी उद्यान विभाग, कृषि कॉलेज रीवा ने बताया छात्र-छात्राएं अनुभावत्मक शिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से फूलों एवं फलों की पौधशाला तैयार कर रहे और भविष्य में उद्यानिकी फसलों की खेती के साथ उसके सह उत्पाद से अपना स्वयं का उद्योग लगाकर अपने रोजगार के साथ साथ दूसरो को भी रोजगार देने की क्षमता रख सकते हैं। भविष्य में अपना स्वयं का रोजगार करके अपने जीवन स्तर को बढ़ा सकते हैं।

गांव-गांव पहुंच रहे कचरा वाहन

## पशु पालन मंत्री ने दिखाई कचरा वाहन को हरी झंडी

**भोपाल।** सुखद एवं खुशहाल जीवन के लिए बेहतर स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। अगर हमारे आस-पास गंदगी है तो हम स्वस्थ कैसे हो सकते हैं। अत: ग्रामीणजन ग्राम में आने वाले कचरा वाहन में ही गीला एवं सूखा कचरा अलग-अलग डालें। स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण के संवाहक बनें। पशुपालन मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने यह बात विकास यात्रा के दौरान बड़वानी जिले के ग्राम बोकराटा में कचरा वाहन को हरी झण्डी दिखाते हुए कही। मंत्री ने ग्रामीणों को शासन की विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर उनसे लाभ लेने के लिये प्रेरित किया। पटेल ने शासन की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को हितलाभों का वितरण करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाते हुए उन्हे बधाई दी। मंत्री ग्राम बोकराटा, कालाखेत, उबादगढ़, चौकी, कुंभखेत, सांवरियापानी, डाबरी में निकाली गई विकास यात्रा में शामिल हुए। विकास यात्रा के दौरान ग्राम उबादगढ़ में पीएम आवास योजना के 10 हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया। ग्राम पंचायत कुंभखेत में आंगनवाड़ी भवन एवं चौपाल निर्माण का भूमि-पूजन, ग्राम बोकराटा में सीसी रोड एवं पाइप पुलिया का लोकार्पण, ग्राम चोकी में चेक डेम एवं स्टाप डेम का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत सिंह पटेल, जिला पंचायत सदस्य बरमा सोलंकी, गीता चौहान, जनपद अध्यक्ष थानसिंग सोलंकी, जनपद सदस्य सरपंच, पंच उपस्थिति थे।

-एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत किया प्रशिक्षित

# बैतूल में मसाला खेती को बढ़ावा देने पढ़ाया दक्षता का पाठ

**बैतूल।** कृषि विज्ञान केंद बैतूल में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत एक दिवसीय उद्यानिकी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में मसालों की कृषि को बढ़ावा देने के लिए जिले के 110 कृषकों को प्रशिक्षित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. टीआर शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक, जनेकृ विवि, जबलपुर एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. एसके पन्नासे, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र छिंदवाड़ा शामिल हुए। कार्यक्रम के आरंभ में केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. व्हीके वर्मा ने मसालों की कृषि के महत्व को रेखांकित किया। साथ ही मसाला फसलों के उत्पादन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जिले की जलवायु अनरूप उत्पादित की जाने वाली मसाला फसलें अदरक, हल्दी, धनिया आदि की विस्तृत जानकारी दी। विशिष्ट अतिथि द्वारा किसानों को हल्दी की उन्नत उत्पादन तकनीक, उन्नत किस्म का प्रशिक्षण दिया गया। आरके कोरी, उप संचालक उद्यानिकी बैतूल ने मसाला फसलों के क्षेत्रफल, संभावनाएं एवं प्रमुख समस्याओं को रेखांकित कर इनके प्रभावी समाधान का आह्वान कृषि विषेषज्ञों से किया।

### प्राकृतिक खेती की प्रदर्शनी भी लगाई

डॉ. आरके झाड़े, उद्यानिकी वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केन्द्र छिंदवाड़ा ने लहसुन-प्याज उत्पादन प्रौद्योगिकी, केन्द्र की शस्य वैज्ञानिक डॉ. मेघा दुबे ने खरपतवार प्रबंधन एवं पोषक तत्व प्रबंधन, उद्यानिकी वैज्ञानिक डॉ. एसएस गौतम ने अदरक उत्पादन प्रौद्योगिकी, पौध संरक्षण वैज्ञानिक आरडी बारपेटे ने मसाला फसलों में पौध संरक्षण और खाद्य वैज्ञानिक डॉ. एमपी इंगले ने मसाला फसलों का प्रसंस्करण की जानकारी दी। इस अवसर पर केन्द्र के प्रांगण में जैविक हाट बाजार एवं प्राकृतिक खेती की प्रदर्शनी भी लगाई गई।

## -हलमा उत्सवः मुख्यमंत्री ने की घोषणा-अब हलमा प्रदेश स्तर पर होगा लागू

# झाबुआः चार घंटे में भगीरथों ने बनाई 35 हजार जल संरचनाएं

» दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाएगी जनजातीय वर्ग की हलमा परम्परा

» जनता की भावना और सरकार के साधन मिल जाए तो सारा काम होगा आसान

**झाबुआ।**

हलमा यानी सामूहिक श्रमदान की समृद्ध परंपरा का अनूठा दृश्य झाबुआ में देखने को मिला। स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में पहुंचे। वह हेलीकाप्टर से गैंती लेकर उतरे। ग्रामीणों के साथ उन्होंने श्रमदान भी किया। हाथीपावा की पहाड़ी पर भगीरथों ने चार घंटे में 35 हजार जल संरचनाएं बना दीं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर घोषणा की कि इस आयोजन को अब प्रदेश स्तर पर लागू किया जाएगा, क्योंकि इससे ही ग्लोबल वार्मिंग से निपटा जा सकता है। साहूकारों ने तय समय से ज्यादा ब्याज लिया तो उनकी भी खैर नहीं। जनजातीय समुदाय को शोषण से बचाने व गांव के संसाधन पर उनका हक सुनिश्चित करने के लिए पेसा एक्ट लागू किया गया है।

हलमा की परम्परा को समूचे मध्यप्रदेश में विस्तारित किया जाएगा। हमारे झाबुआ और अलीराजपुर जिले की हलमा परम्परा अद्भुत है। जनजातीय भाई-बहनों द्वारा सहभागिता की यह परम्परा आज दुनिया को ग्लोबलवार्मिंग से बचा सकती है। इस परम्परा से दुनिया को सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया को बचाना है तो अकेले सरकार नहीं बचा सकती। हलमा जैसी परम्परा में सरकार और समाज मिल कर खड़े हो जाएं तो हम दुनिया को बचाने का संदेश हलमा से दे सकते हैं। हलमा हमको सिखाता है कि कैसे हम मेहनत करें और जनता की भावना के साथ सरकार के साधन मिल कर काम को आसान बनाया जाए।
**शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री**

### यह रहा खास

» 07 बजे सुबह से ही ग्रामीण पहाड़ी पर चढ़ने लगे थे
» 11 बजे तक चलता रहा हलमा
» 40 हजार की संख्या का दावा
» 3 मीटर लंबी और 1.75 मीटर चौड़ी एक जल संरचना
» 200 लीटर पानी एक बार में रुकेगा
» 28 करोड़ लीटर पानी वर्षाकाल में संग्रहित होगा

**ऐसी है जल संरचना**

### ऐसे हुआ कार्यक्रम

» 12 जोन में ग्रामीणों को विभाजित किया गया
» 12 रंग के झंडों के साथ हुआ श्रमदान
» 2009 से यह आयोजन हो रहा

### यह है लाभ

» वर्षाकाल में पानी बहकर नहीं जा सकेगा
» पानी संग्रहित होने से जल स्तर बढ़ेगा
» बोरिंग, कुएं व अन्य स्रोत रिचार्ज होंगे
» सामाजिक हित की भावनाओं का विस्तार होगा

### यह है हलमा

जनजातीय समुदाय के बीच वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है कि यदि गांव का व्यक्ति कोई कार्य करवाना चाहता है और उसके पास पैसे या संसाधन की कमी है तो गांववाले निस्वार्थ भाव से उसकी मदद के लिए जाते हैं। इसे हलमा कहा जाता है। सदियों पुरानी यह परंपरा चलन में कम हो गई थी, जिसे शिवगंगा संगठन ने वापस ला दिया है। संगठन हलमा करवाते हुए जल संरक्षण सहित समाज हित कार्य इस प्रथा के माध्यम से करवा रहा है।

# मध्य प्रदेश में आदिवासियों को पशुपालन से जोड़ा जाएगा

**भोपाल।** प्रदेश में आदिवासियों (विशेष पिछड़ी जनजाति) को पशुपालन से जोड़कर आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए सरकार दो दुधारू पशु उपलब्ध कराएगी। इन्हें खरीदने में जो राशि खर्च होगी, उसकी भरपाई 90 प्रतिशत अनुदान देकर की जाएगी। इस योजना के लिए एक मार्च को प्रस्तुत होने वाले बजट में प्रावधान किया जाएगा। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा, भारिया और सहरिया) वर्ग को आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इन वर्गों की महिलाओं को एक हजार रुपए विशेष पोषण आहार भत्ता दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके लिए योजना को मंजूरी दे चुके हैं। अब बजट प्रावधान किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य सितंबर 2023 तक सभी पात्र हितग्राहियों के प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कराने का है। इसके लिए वर्तमान बजट में सर्वाधिक दस हजार करोड़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय विकास एवं आवास विभाग को आवंटित किए गए थे। वर्ष 2023-24 में भी दोनों विभागों को लक्ष्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, जल शक्ति मिशन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को भी पांच हजार करोड़ से अधिक आवंटित किए जाएंगे ताकि निर्धारित लक्ष्य समयसीमा में पूरे हो सकें।

» सरकार उपलब्ध कराएगी दो दुधारू पशु
» विशेष पिछड़ी जनजाति को दो दुधारू पशु मिलेंगे
» 90 प्रतिशत खर्च उठाएगी सरकार
» एक मार्च को प्रस्तुत होने वाले बजट में होगा प्रावधान

## -क्लस्टर प्रदर्शनों से होगा उन्नत प्रजाति और नई तकनीक का प्रसार

# नई प्रजाति की सरसों-मसूर में माह-कीटों नहीं दिखा प्रकोप

**शिवपुरी।**

गत दिवस राजमाता विजयाराजे कृषि विवि, ग्वालियर के निदेशालय विस्तार सेवाएं से आए कृषि वैज्ञानिक डॉ. नीरज हाडा, कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एमके भार्गव, डॉ. एसएस कुशवाह, वैज्ञानिक डॉ. जेसी गुप्ता प्रभारी अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन दलहन, वैज्ञानिक डॉ. एएल बसेड़िया, प्रभारी अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन तिलहन द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र के द्वारा चयनित कलस्टरों के ग्राम किरौली, रातौर, पिपरसमां आदि में सरसों प्रजाति डीआरएमआर-गिरिराज का निरीक्षण एवं आकलन किया, जो किसानों के खेत पर बहुत अच्छी परिणाम आ रहे हैं। किसानों से चर्चा करने के दौरान किसानों ने कहा कि यह प्रजाति देखने में तो अच्छी है ही, साथ ही इसमें माहू कम आया है या नहीं के बराबर आया है। इसी क्रम में मसूर के खेतों का भी निरीक्षण कर किसानों से चर्चा की। जिसमें रातौर के किसान राजवीर जाटव और पिपरसमां के किसान अशोक धाकड़ से चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि मसूर की प्रजाति-आईपीएल 316 बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है। इसमें किसी प्रकार के रोग, कीड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसमें 3 से 4 क्विंटल प्रति बीघे के मान से उपज निकलने की संभावना है। आगे इस प्रजाति के बीज को मंडी में न बेचने की बात कही है। भविष्य में शिवपुरी जिले के आस-पास के किसानों को उक्त बीज को बेच कर इस प्रजाति को और आगे बढ़ाने की बात कही गई।

## -रजिस्ट्रेशन पहले आओ पहले पाओ आधार पर होगा

# मशरूम की तकनीकी पर एक मार्च से प्रशिक्षण

**नरसिंहपुर।**

कृषि विज्ञान केन्द्र नरसिंहपुर को वर्ष 2022-23 में कौशल विकास परियोजना अंतर्गत 20 प्रशिक्षार्थियों को मशरूम उत्पादन तकनीकी पर प्रशिक्षण देने के लिए संचालक, आईसीएआर-अटारी 9जी जोन, जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि, जबलपुर द्वारा एक माह का प्रशिक्षण आयोजन करने के लिए निर्देशित किया गया है। मशरूम उत्पादन के रोजगारमुखी समस्त तकनीकि जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए इच्छुक प्रशिक्षार्थी अपने आवेदन पत्र के साथ, दो पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र छायाप्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति मोबाइल नंबर सहित प्रशिक्षक वैज्ञानिक डॉ. एसआर शर्मा के पास या कार्यालय में जमा करें। रजिस्ट्रेशन पहले प्राप्त प्रार्थना पत्र को पहले आओ पहले पाओ आधार पर किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान खाने वाले मशरूम जैसे आयस्टर ढिंगरी मशरूम, बटन मशरूम, पुआल एवं सफेद मशरूम उत्पादन पर प्रशिक्षण देने के साथ ही मशरूम विक्रय संस्थानों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। मशरूम में लगने वाले रोग/कीट की पहचान, कारण-निदान के बारे में प्रशिक्षण के दौरान जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षार्थियों को वितरित की जाने वाली बुकलेट में भी उपरोक्त जानकारी वितरित की जाएगी। प्रशिक्षण एक मार्च से कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर में आयोजित किया जाएगा।

## सरसों की फसल में किसानों को कम लगात में मिल रहा है अधिक मुनाफा

# इस बार चार क्विंटल प्रति बीघा हुआ सरसों का उत्पादन, किसानों को भाव भी मिल रहा अच्छा

शिवपुरी/श्योपुर। खेमराज गौर्य

जिले में गेहूं की बंपर पैदावार होती है, लेकिन इस बार किसानों गेहूं की फसल छोड़कर सरसों और चना की फसल की है। इसके पीछे कारण यह है कि, पिछले तीन-चार साल से सरसों के दाम में बढ़ोत्तरी हुई है, इसलिए किसानों ने सरसों की फसल की ओर रूख किया है। पिछले कई सालों की तुलना में सरसों की फसल का रकबा 60 हजार 150 हेक्टेयर तक बढ़ गया है। इस बार सरसों की पैदावार में अच्छी हुई है 4 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से उत्पादन हो रहा है। इसलिए किसान को 1 बीघा में 5500 रुपये के खर्चे पर 22 हजार का मुनाफा हो रहा है।

उल्लेखित है कि, श्योपुर जिले में किसान गेहूं, बाजरा, धान की खेती अधिक करते हैं। बंपर उपज के बाद किसानों को दाम सही नहीं मिल पाते हैं, शुरू में श्योपुर में धान का रकबा महज 4 से 5 हेक्टेयर था, लेकिन वर्तमान में अधिक हो गया है। अब गेहूं, सरसों की फसल कर रहे हैं। सोंईकलां क्षेत्र में कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने 20 साल के बाद खेतों में सरसों की फसल की है।

गेहूं की फसल में ज्यादा मेहनत और लागत लगती है, लेकिन सरसों में कम लागत में अच्छा मुनाफ मिल रहा है।धान की फसल करने के बाद तीन साल से गेहूं की फसल न करते हुए सरसों की फसल कर रहा हूं, जिसमें अच्छा मुनाफा हो रहा है। सरसों की कटाई के बाद मूंग फसल करूगां जिसमें 15 हजार बीघा की मुनाफ होगा।

**तुलसीराम गौड़, किसान, निवासी ददूनी**

इस बार 1 बीघा में 4 क्विंटल सरसों उत्पादन हुआ है, और किसानों को मंडी में भाव मिल रहा है। सरसों ऐसी फसल जिसमें लागत कम और मुनाफा अधिक होता है। चार साल में सरसों का रकबा दोगुना हो गया है। इस बार 60150 में सरसों हुई बोई गई थी। एमएसपी भी बड़ी है। किसानों का तिलहन अधिक करना चाहिए।

**विशंभर गौड़, जिला पररामर्शदाता, कृषि विभाग**

### इस तरह बढ़ा सरसों का रकबा

| वर्ष | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 95840 | 88530 | 77350 | 74000 |
| सरसों | 37050 | 30590 | 57350 | 60150 |
| चना | 21300 | 29980 | 27430 | 30200 |

### चार साल में गेहूं, चना, सरसों की एमएसपी

| एमएसपी | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 1925 | 1975 | 2015 | 2125 |
| चना | 4875 | 5100 | 5230 | 5335 |
| सरसों | 4425 | 4650 | 5050 | 5450 |

### सरसों में लागत कम मुनाफा ज्यादा

सरसों के भाव में तेजी होने के चलते इस साल समूचे क्षेत्र में सरसों की बोवनी काफी ज्यादा हुई है। जिले में सरसों का रकबा बीते वर्ष की तुलना में काफी बढ़ गया है। किसान नेता नाथूलाल मीणा कहते हैं कि, तिलहन के इतिहास में अब तक सरसों, लाही के भाव में कभी भी इतना उछाल नहीं आया पहली बार भाव दोगुने से भी अधिक पहुंचने से किसान अब सरसों की खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इस समय सरसों का भाव 5800 से 6000 हजार रुपए प्रति क्विंटल के बीच चल रहा है, और इसके अलावा सरसों में लागत और मेहनत भी कम आती है। प्रति एक हेक्टेयर में 5500 रुपए का खर्च आता है, इसलिए भी किसान अब अच्छा मुनाफा की संभावना देखकर मंडी में फसल बेचने आ रहे हैं।

## केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किया राष्ट्रीय बागवानी मेले का शुभारंभ

# किसानों की आय दोगुनी करने में बागवानी की महत्वपूर्ण भूमिका

श्योपुर। जागत गांव हमार

किसानों की आय दोगुनी करने के साथ आवश्यक पोषण सुरक्षा पूर्ति करने में बागवानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बागवानी फसलों के उत्पादन व उपलब्धता में तेजी से हो रही वृद्धि देश की पोषण सुरक्षा के बीच की खाई को पाटने में मदद करेगी। यह बात केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तहत भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरू द्वारा उत्पादक किसानों व अन्य हितधारकों के लाभ के लिए विकसित नवीनतम तकनीकों को प्रदर्शित करने व उनकी आत्मनिर्भरता के लिए अभिनव बागवानी पर आयोजित चार दिनी राष्ट्रीय बागवानी मेले का शुभारंभ करते हुए कही।

केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि बागवानी उत्पादन वर्ष 1950-51 के 25 मिलियन टन से 13 गुना बढ़कर 2020-21 के दौरान 331 मिलियन टन हो गया, जो खाद्यान्न उत्पादन से भी अधिक है।18 प्रतिशत क्षेत्रफल से यह क्षेत्र कृषि सकल घरेलू उत्पाद में सकल मूल्य का लगभग 33 प्रतिशत योगदान देता है। इस क्षेत्र को आर्थिक विकास के चालक के रूप में माना जा रहा है और धीरे-धीरे एक संगठित उद्योग में बदल रहा है, जो बीज-व्यवसाय, मूल्यवर्धन व निर्यात से जुड़ा हुआ है। कृषि उत्पादों के चार लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निर्यात में बागवानी का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार खेती-किसानी को प्राथमिकता देती है, इसलिए वर्ष 2023-24 के बजट में भी कृषि एवं किसान कल्याण के लिए अनेक प्रमुख प्रावधान किए गए। बजट का उद्देश्य गरीबों व मध्यम वर्ग, महिलाओं व युवाओं के अलावा किसानों का समावेशी और व्यापक विकास करना है। यह कृषि को प्रौद्योगिकी से जोड़कर कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने पर जोर देता है ताकि किसानों को दीर्घावधि में व्यापक लाभ मिल सके।

### 54 बागवानी फसलों पर हो रहा काम

तोमर ने सराहना करते हुए कहा कि आईआईएचआर देश के प्रमुख संस्थानों में एक होने के नाते बड़े पैमाने पर किसानों के सतत व आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए बागवानी फसलों में बुनियादी अनुसंधान करने के लिए जाना जाता है और आईआईएचआर में विकसित प्रौद्योगिकियां देश में लगातार बढ़ते बागवानी क्षेत्र में सालाना 30 हजार करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दे रही हैं। संस्थान 54 बागवानी फसलों पर काम कर रहा है और विभिन्न हितधारकों के लाभ के लिए बागवानी फसलों की 300 से अधिक किस्में और संकर विकसित किए गए हैं, जो उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित अन्य क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। संस्थान द्वारा कटहल व इमली के संरक्षक किसानों की आजीविका के साथ जैव विविधता को जोड़ना उल्लेखनीय है और इसे अन्य बागवानी फसलों में दोहराया जा सकता है। संस्थान ने विदेशी फलों की फसलों (कमलम, एवोकैडो, मैंगोस्टीन, रामबूटन) पर काम शुरू किया है, जिससे आयात घटाने में मदद होगी। साथ ही संस्थान द्वारा विकसित तरबूज की नई किस्म इसके बीजों के आयात को कम करने में सहायक होगी।

## प्रदेश के 38 लाख बिजली उपभोक्ताओं को 791 करोड़ की दी गई सब्सिडी

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में राज्य शासन द्वारा अटल गृह ज्योति योजना में माह नवंबर 2022 में 29 लाख 30 हजार 552 घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 150 करोड़ 7 लाख रुपए एवं अटल किसान ज्योति योजना में 8 लाख 77 हजार 943 कृषि उपभोक्ताओं को 641 करोड़ 43 लाख की सब्सिडी दी गई है।

## मप्र माटीकला बोर्ड प्रबंधकारिणी की बैठक सम्पन्न

**भोपाल।** मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड प्रबंधकारिणी की बैठक अध्यक्ष रामदयाल प्रजापति की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में बोर्ड की मुख्य कार्यपलन अधिकारी अनुभा श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बोर्ड के अध्यक्ष प्रजापति ने कहा है कि माटीकला बोर्ड के माध्यम से देश की परम्परागत माटी शिल्प को समृद्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माटी के माध्यम से रोजगार चलाने वाले प्रजापति वर्ग के आर्थिक और सामाजिक विकास का कार्य भी बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बोर्ड की गतिविधियों से समाज के अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की आवश्यकता बतलाई। बैठक में विगत वर्षों में मप्र माटीकला बोर्ड द्वारा सम्पन्न किए गए कार्यों एवं गतिविधियों पर भी चर्चा की गई एवं सभा द्वारा वित्तीय वर्ष की लक्ष्य पूर्ति पर संतोष व्यक्त किया गया।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)